Date: 08 Dec 2025

Source:- जनसत्ता

गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग

दिल्ली के चार पर्यटकों समेत 25 लोगों की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

उत्तरी गोवा के एक नाइट क्लब में शनिवार आधी रात के बाद भीषण आग लग जाने से दिल्ली के चार पर्यटकों समेत 25 लोगों की मौत हो गई और छह अन्य लोग घायल हो गए। दिल्ली के चार पर्यटकों में से तीन एक ही परिवार के थे। वहीं, जिन 20 कर्मचारियों की इस हादसे में मौत हुई, उनमें से उत्तराखंड के पांच क्लब कर्मचारी भी थे। सभी 25 पीड़ितों की पहचान कर ली गई है। कुल मिलाकर मृतकों में 20 कर्मचारी और पांच पर्यटक शामिल हैं। हादसे में मरा एक पर्यटक कर्नाटक से था।

पुलिस ने बताया कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा, प्रबंधक और कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा अरपोरा–नागोआ पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर को हिरासत में लिया गया, जिन्होंने 2013 में परिसर के लिए व्यापार लाइसेंस जारी किया था। वहीं, अधिकारियों ने अरपोरा नाइट क्लब के संचालकों के एक और उद्यम वागाटोर में 'रोमियो लेन' को सील किया।

राज्य सरकार ने 25 मतकों की सूची जारी की। सूची के अनुसार, मृतकों में से 20 नाइट क्लब के कर्मचारी थे, जिनमें उत्तराखंड के पांच, नेपाल के चार, झारखंड और असम के तीन–तीन, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के दो–दो और पश्चिम बंगाल का एक व्यक्ति शामिल है।

मृतकों (कर्मचारियों) में सबसे अधिक संख्या उत्तराखंड के लोगों की है, जिनकी पहचान जितेंद्र सिंह, सतीश सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुमित नेगी और मनीष सिंह के रूप में हुई है। चार नेपाली नागरिकों की पहचान चूर्ण बहादुर पुन, विवेक कटवाल, सबिन और सुदीप के रूप में हुई है। मृतकों में महाराष्ट्र के डोमिनिक और मनोज जोरा, जबकि उत्तर प्रदेश के रोहन सिंह और सुनील कुमार शामिल हैं। दार्जिलिंग

बाकी पेज 8 पर

उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव के नाइट क्लब में आधी रात को आग लग गई।

दिल्ली के एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

गोवा के नाइट क्लब में शनिवार देर रात लगी आग में दिल्ली के चार पर्यटकों की मौत हो गई। पांचवां पर्यटक कर्नाटक का था। दिल्ली के तीन लोग एक ही परिवार के थे। इनकी पहचान सरोज जोशी, अनीता जोशी और कमला जोशी के रूप में उनकी रिश्तेदार भावना जोशी ने रविवार को की। दिल्ली के चौथे पर्यटक के पहचान विनोद कुमार के रूप में हुई। इस घटना में जान गंवाने वाले एक अन्य पर्यटक की पहचान कर्नाटक के इशाक के रूप में उनके पिता एमडी हुसैन ने की।

पुलिस ने नाइट क्लब के दो मालिकों, उसके प्रबंधक और कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और अरपोरा–नागोआ पंचायत के सरपंच को हिरासत में लिया है।

क्लब के मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, महाप्रबंधक विवेक सिंह, बार प्रबंधक राजीव सिंघानिया और द्वार प्रबंधक रियांशु ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है।

तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया जिनमें तत्कालीन पंचायत निदेशक सिद्धि तुषार हरलंकर, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में तत्कालीन सदस्य सचिव शमिला मोंटेइरो और ग्राम पंचायत अरपोरा–नागोआ के तत्कालीन सचिव रघुवीर बागकर शामिल हैं।

लोकसभा में आज प्रधानमंत्री वंदे मातरम् पर चर्चा शुरू करेंगे

विपक्ष से प्रियंका व गोगोई चर्चा में शामिल होंगे, राज्यसभा में कल गृहमंत्री अमित शाह करेंगे शुरुआत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसमें राष्ट्रीय गीत के बारे में कई महत्त्वपूर्ण और अज्ञात पहलुओं के सामने आने की संभावना है।

लोकसभा में 'राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा' सोमवार के लिए सूचीबद्ध है और इस पर बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा में दूसरे वक्ता होंगे। इस चर्चा में सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी सहित अन्य सदस्य भी शामिल होंगे, जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगले दिन चुनाव सुधारों पर बोलेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर बैज प्रदान किया गया।

लोकसभा में 'राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा' सोमवार के लिए सूचीबद्ध है और इस पर बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। *प्रधानमंत्री* मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उस पर 1937 में इस गीत से प्रमुख छंदों को हटाने और विभाजन के बीज बोने का आरोप लगाया था।

राज्यसभा में मंगलवार को गृह मंत्री इस पर चर्चा शुरू करेंगे। संसद में यह चर्चा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित और जदुनाथ भट्टाचार्य द्वारा संगीतबद्ध वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर वर्ष भर आयोजित होने वाले समारोह का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उस पर 1937 में इस गीत से प्रमुख छंदों को हटाने और विभाजन के बीज बोने का आरोप लगाया था।

सात नवंबर को, मोदी ने वंदे मातरम् के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में वर्ष भर आयोजित होने वाले समारोहों की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और छात्रों के बीच इस गीत के महत्व के बाकी पेज 8 पर

इंडिगो संकट पर सरकार ने कहा

अब तक 610 करोड़ की रकम लौटाई गई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

इंडिगो ने रद्द या अत्यधिक विलंबित उड़ानों के लिए अब तक 610 करोड़ रुपए के रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर ली है और शनिवार तक 3,000 नग सामान यात्रियों तक पहुंचा दिया गया है।

सरकार ने रविवार को कहा कि देश का विमानन नेटवर्क तेजी से सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है और परिचालन पूरी तरह स्थिर होने तक सभी सुधारात्मक कदम लागू रहेंगे। सरकार ने शनिवार को एयरलाइन को निर्देश दिया था कि रद्द उड़ानों से संबंधित टिकटों का रिफंड रविवार शाम तक पूरा किया जाए और यात्रियों के छूटे हुए सामान को अगले 48 घंटे के भीतर उन तक पहुंचाया जाए। मंत्रालय ने कहा कि इंडिगो के हालिया परिचालन संकट के कारण उत्पन्न व्यवधान को दूर करने के लिए तेज और प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिससे यात्रियों को आगे कोई असुविधा न हो।

नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि इंडिगो अब तक 610 करोड़ रुपए का रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर चुका है। रद्द उड़ानों से प्रभावित यात्रियों के यात्रा पुनर्निर्धारण में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

यात्रियों की सहायता के लिए विशेष सहायता केंद्र बनाए गए हैं, जिससे रिफंड और दोबारा बुकिंग से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान हो सके। मंत्रालय ने बताया कि देशभर में हवाई सेवाएं तेजी से सामान्य हो रही हैं।

अन्य सभी घरेलू विमानन कंपनियां सुचारु रूप से उड़ानें संचालित कर रही हैं, जबकि इंडिगो का प्रदर्शन भी लगातार सुधर रहा है। इंडिगो की उड़ानें शुक्रवार को 706 से बढ़कर शनिवार को 1,565 हो गईं।

संकट का असर राजस्थान के पर्यटन पर भी, लोगों ने बुकिंग रद्द करवाई

निजी विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ानों को लेकर उपजे संकट का असर राजस्थान के पर्यटन सीजन पर भी पड़ा है। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने रविवार को कहा कि इस संकट के कारण पर्यटकों की आवक घटी है और कई जगह होटल तथा यात्रा परिचालक प्रभावित हैं। दिसंबर के महीने को राजस्थान में पर्यटकों के लिहाज से सबसे व्यस्त समय में से एक माना जाता है। जयपुर के टूर आपरेटर संजय कौशिक ने कहा कि राजस्थान में व्यस्त सीजन10 दिसंबर से पांच जनवरी तक होता है। इसमें क्रिसमस और नववर्ष के जश्न जैसे मौके आते हैं तथा मौजूदा इंडिगो संकट ने इसे बुरी तरह प्रभावित किया है।

समृद्ध देशों में दरकिनार होते प्रवासी

जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभाली है, तब से न केवल अमेरिका, बल्कि उसके साथी अमीर देश कनाडा, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया आदि भी प्रवासी नागरिकों को अपनी सीमा से निष्कासित करने की कोशिश में लगे हैं।

सुरेश सेठ

भारत ही नहीं, बल्कि तीसरी दुनिया के देशों की श्रम शक्ति और युवा शक्ति समृद्ध देशों में किसी न किसी तरीके से प्रवेश कर रातों-रात अपनी आर्थिक स्थिति बदल लेना चाहती है। सवाल है कि पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया का वर्गीकरण कैसे होता है? द्वितीय महायुद्ध के बाद से देखें, तो पहली दुनिया समृद्ध पश्चिमी या यूरोपीय देशों और अमेरिका की है। दूसरी दुनिया रूस समर्थक देशों की और तीसरी दुनिया पश्चिमी देशों से आजाद हुए या अपनी गरीबी से जूझते देशों की है। आर्थिक विकास शास्त्र ने इसका वर्गीकरण विकासवादी व्यवस्था के रूप में किया है। यानी पहली दुनिया विकसित देशों की, दूसरी दुनिया विकासशील देशों की जिनमें भारत भी शामिल है और तीसरी दुनिया अविकसित देशों की है जिनमें गरीब देश शामिल हैं।

तीसरी दुनिया की युवा शक्ति पहली दुनिया या पश्चिमी देशों की ओर भागती है, क्योंकि जिस देश में वे रहते हैं, वहां उन्हें अपने सपने साकार होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। धनी होने का सपना देखते हजारों नौजवान हर वर्ष इन देशों में जाकर काम करना चाहते हैं। अगर वैध तरीके से न जा सके, तो अवैध तरीके से या अपनी जान हथेली पर रख कर भी ये नौजवान समृद्ध देशों में प्रवेश करना चाहते हैं। जो रास्ते में मर-खप गए, उनका कोई अता-पता नहीं चलता। जो किसी तरह विदेश चले भी गए, तो वे वहां भी वे दोयम दर्जे की जिंदगी जीते हैं और किसी न किसी प्रकार अपने पांच साल पूरे कर ग्रीन कार्ड पाने की इच्छा रखते हैं।

जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभाली है, तब से न केवल अमेरिका, बल्कि उसके साथी अमीर देश कनाडा, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया आदि भी आप्रवासी नागरिकों को (खासतौर से उन उन्नीस देशों के नागरिकों, जिनके बारे में ट्रंप ने सूची जारी की है और यह कहा है कि उनके देश में गैर-कानूनी घटनाओं से लेकर हिंसक वारदात यही लोग करते हैं) अपनी सीमा से निष्कासित करने की कोशिश में लगे हैं। इन सभी देशों में भारतीयों की भी पर्याप्त संख्या है। उनको हथकड़ियों-बेड़ियों में वापस भेजा जा रहा है। इन लोगों का स्वागत करने के लिए अमेरिका तैयार नहीं, बल्कि ट्रंप देश से इनको बाहर करना चाहते हैं। ये यही भारतीय हैं जिनके कौशल और श्रम से अमेरिका का आधार बना है। अभी वाइट हाउस में अफगानिस्तान के एक शरणार्थी द्वारा की गई गोलीबारी से एक नेशनल गार्ड की मौत हो गई। इस बात से खीझ कर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में गरीब देशों के प्रवासियों का प्रवेश बंद है। वर्तमान आप्रवासियों में से अगर किसी से सुरक्षा को खतरा लगता है तो उसे भी तुरंत उसके देश भेज दिया जाएगा।

अमेरिका की देखादेखी कनाडा ने छात्र वीजा पर सख्ती कर दी है। अब वीजा रद्द करने की दर चूंकि 75 फीसद तक पहुंच गई है, इसलिए नया प्रवेश 40 फीसद तक गिर गया। आज यहां 70 फीसद वीजा आवेदन रद्द हो रहे हैं। वर्ष 2023 में यही दर 32 फीसद थी। ब्रिटेन गए छात्र अपने साथ पहले परिवार ला सकते थे, लेकिन 2025 से वीजा नवीनीकरण में सख्ती बरती जाने लगी। परिवार लाने पर रोक लग गई। इस तरह से कई भारतीय ब्रिटेन छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। आस्ट्रेलिया ने भी इस वर्ष से नई प्रवासन नीति लागू कर दी है जिसमें छात्र वीजा को कठिन बना दिया गया है। वर्ष 2024 में अगर यहां 96 हजार 490 प्रवासी भारतीय छात्र थे, तो इसी वर्ष पहले छह महीनों में यह संख्या कम होकर 87 हजार 600 हो गई। अब जब अपने हित साधने की यह नीति इन समृद्ध देशों ने लागू कर दी है, तो भारतीयों या अन्य 19 गरीब देशों के छात्रों के लिए समृद्ध देशों में प्रवेश बहुत कठिन हो गया है। अमेरिका ने तो और भी कई नियम बना दिए। ग्रीन कार्ड देने की अवधि बढ़ा दी और इसे आसानी से न लागू करने की नीति अपनाई। इस समय इसकी प्रतीक्षा सूची में लगभग दस लाख भारतीय हैं। मगर अमेरिका या अन्य समृद्ध देशों को यह नहीं भूलना चाहिए कि आज उनकी प्रगति और समृद्धि में इन्हीं प्रवासी नागरिकों का खून-पसीना लगा है।

> अमेरिका की देखादेखी कनाडा ने छात्र वीजा पर सख्ती कर दी है और अब वीजा रद्द करने की दर चूंकि 75 फीसद तक पहुंच गई है, इसलिए नया प्रवेश 40 फीसद तक गिर गया। आज यहां 70 फीसद वीजा आवेदन रद्द हो रहे हैं। वर्ष 2023 में यही दर 32 फीसद थी। ब्रिटेन में गए छात्र अपने साथ पहले परिवार ला सकते थे, लेकिन 2025 से वीजा नवीनीकरण में सख्ती बरती जाने लगी। परिवार लाने पर रोक लग गई। इस तरह से कई भारतीय ब्रिटेन छोड़ने पर मजबूर हो गए। आस्ट्रेलिया ने भी इस वर्ष से नई प्रवासन नीति लागू कर दी है जिसमें छात्र वीजा को कठिन बना दिया गया है।

एक राजनीतिक संदेश यूरोप, कनाडा और आस्ट्रेलिया सरकार को भी चला गया कि वे प्रवासियों को आने से रोकें। अगर यह श्रम शक्ति उत्पादन प्रक्रिया से बाहर हो जाती है, तो इन देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। अमेरिका आज 30 ट्रिलियन डालर की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, तो उसका 20 फीसद हिस्सा इन आप्रवासियों की मेहनत पर ही टिका है। तीन प्रकार के प्रवासी अमेरिका या समृद्ध देशों में पाए जाते हैं। भारतीय, चीनी और लैटिन अमेरिकी। गौरतलब है कि इन प्रवासी नागरिकों की श्रम शक्ति सस्ती है। आर्थिक विश्लेषक बताते हैं कि 15 अमेरिकी राज्यों की अर्थव्यवस्था अधिकतर इन्हीं श्रमिकों की दिन-रात की मेहनत पर निर्भर करती है। हालांकि इन राज्यों में अमीरी के साथ-साथ बंदूक संस्कृति भी पनप गई है। फिरौती मांगने का धंधा इन राज्यों में है ही। जहां 15 राज्य इन आप्रवासियों पर लगभग 40 फीसद तक निर्भर हैं। ये आप्रवासी बहुत ईमानदारी से और मेहनत कर-के जिंदगी जीते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका में कुल अपराध दर के मुताबिक ये प्रवासी, स्थानीय नागरिकों की अपेक्षा अपराध में कम ही लिप्त पाए गए। अब ट्रंप ने इन्हीं प्रवासियों को रोकने के आदेश पर मंजूरी लेने की इच्छा जाहिर कर दी है।

हालांकि भारत की युवा शक्ति और अन्य उभरते देशों की नौजवान पीढ़ी विदेश को अपना एकमात्र मोक्ष द्वार नहीं मानती। तीसरी दुनिया के जिन देशों में जो 'जेन-जी' वाली पीढ़ी उभर कर आ गई है, वह अपने देश में ही यथोचित रोजगार और गरिमा से जीना चाहती है। वह इन समृद्ध देशों के रहम पर दोयम दर्जे की जिंदगी अपनाने के लिए इनका सहारा नहीं लेना चाहती। दूसरी ओर यह भी एक सच है कि कुछ देशों में आतंकवादियों के अड्डे हैं और उनके लिए सरकारों का अप्रत्यक्ष सहयोग है, नहीं तो वहां छिपे आतंकी इतनी आसानी से भारत विरोधी गतिविधियां कैसे चलाते? इन देशों की अपनी समृद्धि भी हाड़तोड़ मेहनत करने वाले आप्रवासी नागरिकों की वजह से है, मगर आज कई बड़े देशों ने अपने यहां रह रहे प्रवासी नागरिकों का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्हें हर दिन अपनी धरती से निष्कासित करने की धमकी देते हैं। जबकि उनके परिश्रम के बूते ही अमेरिका वर्षों से आर्थिक शक्ति के रूप में दुनिया के शीर्ष पर है।

अब भी अमेरिका यही कहता है कि वह तकनीकी पेशेवरों का अपने देश में स्वागत करेगा, लेकिन यह नहीं चाहता कि मेहनत-मजदूरी करने वाले लोग अमेरिका में आ जाएं और अपनी मेहनत और कम वेतन के बल पर अमेरिकी जनता की नौकरियों के लिए जारी होने वाला पैसा अपने भुगतान के रूप में हथिया लें। इस पूरे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भारत अब केवल आयात आधारित अर्थव्यवस्था न रहे, अपने पैरों पर और मजबूती से खड़ा हो जाए। स्वावलंबन की इस राह पर युवा पीढ़ी को नौकरियां दें।

प्रश्न – वर्तमान में विकसित देशों से प्रवासियों के निष्कासन के मूल कारणों पर प्रकाश डाले तथा यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करेगी, उल्लेख करें।

38 Marks

जीवाणु संक्रमण की चपेट में आने से झारखंड में 10 काले हिरणों की मौत

रांची, 7 दिसंबर (भाषा)।

झारखंड के जमशेदपुर स्थित एक चिड़ियाघर में जीवाणु संक्रमण के कारण कम से कम 10 काले हिरणों की मौत हो गई है। यह जानकारी एक अधिकारी ने रविवार को दी।

टाटा स्टील जूलाजिकल पार्क (टीएसजेडपी) में हिरणों की मौत एक दिसंबर से छह दिसंबर के बीच हुई। आखिरी हिरण की मौत शनिवार को हुई। टीएसजेडपी के उप निदेशक नईम अख्तर ने बताया कि उद्यान में अब तक दस काले हिरणों की मौत हो चुकी है। हिरण के शव को जांच और मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय भेजा गया है। ऐसा लगता है कि यह जीवाणु संक्रमण के कारण हुआ है। रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय (आरवीसी) की पशु चिकित्सा पैथोलाजी विभाग की सहायक प्राध्यापक प्रज्ञा लकड़ा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। उन्होंने कहा कि संदेह है कि यह एचएस (रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया) है, जो पास्चरेला प्रजाति के बैक्टीरिया से होने वाला एक जीवाणुजनित रोग है। इस रोग को पास्चरेलोसिस भी कहा जाता है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच सोमवार को की जाएगी। टीएसजेडपी में पक्षियों सहित लगभग 370 जानवर हैं। अधिकारी ने बताया कि 10 काले हिरणों की मौतों के बाद, चिड़ियाघर में केवल आठ काले हिरण ही बचे हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा

घरेलू रक्षा उत्पादन 1.51 लाख करोड़ पर पहुंचा, निर्यात 24,000 करोड़ के करीब

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देख रहा है, जो आयात पर निर्भर राष्ट्र से एक उभरते हुए उत्पादक-निर्यातक देश के रूप में सामने आ रहा है। सिंह ने कहा कि देश में एक समय घरेलू स्तर पर हथियार और उपकरण बनाने के लिए मजबूत प्रणाली का अभाव था, लेकिन पिछले दशक के दौरान किए गए निरंतर प्रयासों से स्थिति बदल गई है।

सिंह ने देश के विभिन्न हिस्सों में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा पूरी की गई 125 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद कहा, 'पिछले 10 वर्षों में हमारी कड़ी मेहनत के कारण, हमारा रक्षा उत्पादन, जो 2014 में लगभग 46,000 करोड़ रुपये था, अब बढ़कर रेकार्ड 1.51 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हमारा रक्षा निर्यात, जो 10 वर्ष पहले 1,000 करोड़ रुपए से भी कम था, अब लगभग 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।' केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मिजोरम समेत सात राज्यों में इन परियोजनाओं के तहत 28 सड़कों, 93 पुलों का काम और चार विविध कार्य 5,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हो चुके हैं।

तकनीकी नवाचार में उल्लेखनीय प्रगति के लिए बीआरओ की सराहना करते हुए सिंह ने कहा कि उन्नत इंजीनियरिंग पद्धतियां बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी ला रही हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत 'गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स' के साथ साझेदारी में स्वदेशी रूप से विकसित क्लास-70 माड्यूलर पुलों को बीआरओ द्वारा अपनाने का विशेष उल्लेख किया। पूरी तरह से भारत में निर्मित ये पुल, भारत की इंजीनियरिंग आत्मनिर्भरता में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर हैं।' रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बीआरओ ने 16,690 करोड़ रुपए का रेकार्ड व्यय किया, जो अब तक का सबसे अधिक है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 18,700 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो बीआरओ की क्षमताओं में सरकार के विश्वास को रेखांकित करता है।

तकनीकी नवाचार में उल्लेखनीय प्रगति के लिए बीआरओ की सराहना करते हुए सिंह ने कहा कि उन्नत इंजीनियरिंग पद्धतियां बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी ला रही हैं।

125 बीआरओ परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (ब्यूरो)।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लेह से सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की हाल में पूर्ण हुई 125 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और इन्हें भारत के सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक 'प्रभावी उदाहरण' बताया।

रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण इन परियोजनाओं का निर्माण 5,000 करोड़ की लागत से किया गया है और ये परियोजनाएं लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों तथा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मिजोरम सहित सात राज्यों में फैली हुई हैं। इनमें 28 सड़कें, 93 पुल और चार अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। यह आयोजन बीआरओ के इतिहास में एक ही दिन में किए गए सबसे बड़े और सर्वाधिक मूल्य वाले उद्घाटन का प्रतीक बना।

लद्दाख के उपराज्यपाल कवींद्र गुप्ता ने लेह पहुंचने पर रक्षा मंत्री का स्वागत किया और उद्घाटन समारोह में उनके साथ शामिल हुए। रक्षा मंत्री सिंह ने कहा, 'हमारे सैनिकों का शौर्य और पराक्रम अपने आप में हमारे लिए प्रेरणा है। ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं उन वीरों को राष्ट्र की श्रद्धांजलि हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी।' उन्होंने कहा, सीमावर्ती सड़कें राष्ट्रीय सुरक्षा की जीवन रेखा हैं और बेहतर संपर्क का परिचालन पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

'आपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाएं और अधिक कर सकती थीं, लेकिन हमने संयम बरता'

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (ब्यूरो)।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि आपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बल और भी बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन उन्होंने संयमित और संतुलित प्रतिक्रिया का विकल्प चुना। सिंह ने कहा कि मई में हुए आपरेशन ने भारतीय सेना की क्षमता और अनुशासन को रेखांकित किया, जिन्होंने बिना तनाव बढ़ाये आतंकी खतरों को बेअसर कर दिया।

रक्षामंत्री सिंह ने देश के विभिन्न हिस्सों में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा पूरी की गई 125 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद कहा, 'आपरेशन सिंदूर के दौरान, हमने अपने सशस्त्र बलों, नागरिक प्रशासन और सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों के बीच जो समन्वय देखा, वह अविश्वसनीय था। मैं लद्दाख और सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रत्येक नागरिक के प्रति हमारे सशस्त्र बलों को अपना समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।' सिंह ने कहा, 'यह समन्वय ही हमारी पहचान है। हमारा आपसी बंधन ही हमें दुनिया में सबसे अलग पहचान देता है।'आपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सात मई को शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था।

यूनेस्को की बैठक के लिए लाल किले में अमूर्त विरासत का प्रदर्शन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

भारत ने रविवार शाम लाल किला परिसर में यूनेस्को की एक महत्त्वपूर्ण बैठक के उद्घाटन समारोह के दौरान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया, जिसमें विषय आधारित प्रदर्शनी दीर्घाओं (गैलरी) से लेकर मंचीय कलाओं को शामिल किया गया। यह बैठक 'अमूर्त विरासत के संरक्षण' पर केंद्रित है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर-सरकारी समिति (आइसीएच) का 20वां सत्र आठ से 13 दिसंबर तक लाल किले में आयोजित होगा। यह पहली बार है, जब भारत यूनेस्को पैनल के किसी सत्र की मेजबानी कर रहा है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अल-एनानी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और यूनेस्को में भारत के राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा शामिल हुए। यूनेस्को के मुताबिक, इस सत्र में यूनेस्को की आइसीएच सूचियों में शामिल किए जाने के लिए सदस्य देशों की ओर से पेश नामांकनों की जांच की जाएगी, मौजूदा तत्वों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। विशाल वी शर्मा सत्र की अध्यक्षता करेंगे।

नेल्लोर में स्थापित होगा भारत का पहला गहरे समुद्र सूक्ष्मजीव अनुसंधान केंद्र

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

भारत का पहला गहरे समुद्र में समुद्री सूक्ष्मजीव संग्रह सह अध्ययन केंद्र आंध्र प्रदेश में नेल्लोर के निकट राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइओटी) के समुद्र-तटीय परिसर में स्थापित किया जा रहा है।

इस केंद्र में चरम समुद्री वातावरण में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाएगा। यह अत्याधुनिक सुविधा वैज्ञानिकों को औद्योगिक, जैव-चिकित्सा और पर्यावरणीय अनुप्रयोगों के लिए सूक्ष्मजीवों का अध्ययन, पृथक्करण और संवर्धन करने में सक्षम बनाएगी। गहरे समुद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव जीवन के आदिम रूप हैं, जो उच्च द्रवस्थैतिक दबाव, कम तापमान में रहते हैं।

केंद्र सरकार ने संसद में दी जानकारी | **आंकड़े** | तीन साल में खर्च हुए 170 करोड़ रुपए

राजमार्ग सुरक्षा : प्रचार के लिए पूरा बजट खर्च नहीं कर पाई सरकार

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

देश में राजमार्ग समेत अन्य क्षेत्रों में योजनाओं को लागू करके हादसों में कमी लाने वाली योजनाओं का पूरा पैसा सरकारी एजेंसियां खर्च नही कर पा रही है। यह पैसा राजमार्ग पर दुर्घटना राहत सेवा योजना, असंगठित क्षेत्र के चालकों का प्रशिक्षण और मानव संसाधन, परिवहन प्रणाली में सुधार जैसे कार्यों के लिए किया जाना था। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जनता से संबंधित इन योजनाओं में केंद्र सरकार 170.36 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च नहीं कर पाई है।

केंद्र सरकार की ओर से यह धनराशि राज्यों को उपलब्ध कराई गई थी। आंकड़ों में चौंकाने वाली बात यह है कि सड़क सुरक्षा प्रचार और जागरूकता अभियान जैसी मदों में बीते तीन साल के अंदर कभी भी पूरा पैसा खर्च नहीं किया जा सकता है। इस मद में केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2022-23 में 189.50 में से 68.67 करोड़, 2023- 24 में 130.10 में से 85.04 करोड़ और 2024 25 में 103.50 में से 99.20 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई है। हालांकि सरकारी एजेंसियां खुद मानती है कि व्यापक प्रचार और लोगों को अधिक जागरूक करके ही सड़क दुर्घअना के आंकड़े में कमी लाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त दूसरा पहलू यह भी है कि देश में सार्वजनिक परिवहन की भी कमी है। सार्वजनिक परिवहन की संख्या बढ़ने से आम जनता अपने निजी वाहनों का प्रयोग कम कर सकती है। इसका दोहरा लाभ राज्यों को मिल सकता है। इसमें एक तरफ जहां मार्ग पर वाहनों की बढ़ती संख्या की वजह से भीषण जाम जैसी स्थिति से बचा जा सकेगा, वहीं यह आम जनता को प्रदूषण से भी राहत देगा। लेकिन इस मद में भी आवंटित धनराशि में बीते दो साल से पूरा पैसा खर्च नही किया गया है।

शुरुआत वर्ष 2022 -23 में 15 करोड़ की राशि विभाग के पास थी और मंत्रालय की ओर से 30 करोड़ रुपए खर्च किए थे। जबकि अन्य दो वर्ष में विभाग सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में पैसा खर्च नहीं कर पाया। वर्ष 2023- 24 में 50.00 में से 38 करोड़ रुपए और 2024 25 में 38 में से 16.04 करोड़ रुपए रुपए ही खर्च हो पाए हैं।

ये हैं इंतजाम

राह वीर योजना के तहत सहायता करने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

टक्कर मारकर भागना (हिट ओर रन) के मामले में गंभीर चोट का मुआवजा 12500 से बढ़ाकर 50 हजार रुपए तथा मृत्यु होने पर 25 हजार से दो लाख रुपए तक के मुआवजे का प्रावधान किया है।

पूर्ण हो चुके राजमार्ग के टोल पर पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बूलेंस सेवा का प्रावधान किया गया है।

हर दिन होती है औसतन 485 मौत

सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2024 में सड़क हादसों में 177 लाख लोगों की मौत हुई है। यह औसतन हर दिन 485 मौत हैं। यह आंकड़ा बीते 2023 की तुलना में 2.3 फीसद अधिक है। फरवरी 2020 में सड़क सुरक्षा पर तीसरे वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में सड़क सुरक्षा पर स्टाक होम घोषणा में सरकार ने दावा किया है कि देश में 2030 पचास फीसद तक सड़क दुर्घटना व चोटों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भारत स्टाकहोम घोषणा का हस्ताक्षकर्ता है। विश्व सड़क सांख्यिकी के अनुसार चीन में प्रति लाख आबादी पर मृत्युदर 4.3 फीसद है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की तुलना में यह दर 12.76 फीसद है जबकि भारत की दर 11.89 फीसद है।

राष्ट्रमंडल खेल 2030 में हाकी की मजबूती से वापसी का दावा | साक्षात्कार | एफआइएच अध्यक्ष ने कहा, सरकार का ध्यान खेलों पर

ओलंपिक 2036 की मेजबानी अब दूर की बात नहीं

चेन्नई, 7 दिसंबर (भाषा)।

भारत की मेजबानी में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2030 में हाकी की मजबूती से वापसी का दावा करते हुए अंतरराष्ट्रीय हाकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम ने कहा कि खेलों पर भारत सरकार के फोकस को देखते हुए ओलंपिक की मेजबानी अब दूर की बात नहीं है। भारत को दो दशक बाद राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली है जो 2030 में अहमदाबाद में आयोजित होंगे जिसे 2036 ओलंपिक की भारत की दावेदारी पुख्ता करने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।

जूनियर हाकी विश्व कप से इतर भारत की ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी के बारे में पूछने पर इकराम ने कहा, 'हमें इस तरह की उम्मीदवारी पसंद है और यह अच्छा भी है क्योंकि इसमें अलग हितधारक और प्रतिस्पर्धी होंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2030 भी भारत में हो रहे है। इस समय भारत सरकार का फोकस खेलों और खेलों की मेजबानी पर है लिहाजा ओलंपिक की मेजबानी बहुत दूर की बात नहीं है।'

अंतरराष्ट्रीय हाकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम ने विश्वास जताया कि 2030 में हाकी की मजबूती से वापसी होगी। उन्होंने कहा, हाकी राष्ट्रमंडल का हिस्सा रही है और हमेशा रहेगी। हमारी राष्ट्रमंडल खेल से लगातार अच्छी बातचीत हो रही है और 2030 में हाकी की और मजबूती से वापसी होगी।'

ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में बजट में कटौती के लिए कई खेलों को रोस्टर से हटाया गया है जिनमें हाकी भी शामिल है। एफआइएच अध्यक्ष ने विश्वास जताया कि 2030 में हाकी की मजबूती से वापसी होगी। उन्होंने कहा, 'अगले साल होने वाले खेल राष्ट्रमंडल खेल के लिए काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण हैं। लेकिन हाकी राष्ट्रमंडल का हिस्सा रही है और हमेशा रहेगी। हमारी राष्ट्रमंडल खेल से लगातार अच्छी बातचीत हो रही है और 2030 में हाकी की और मजबूती से वापसी होगी।'

व्यावसायिक दृष्टि से भारत को वैश्विक हाकी का महत्त्वपूर्ण साझेदार बताते हुए एफआइएच अध्यक्ष ने कहा कि खेल को क्रिकेट या बाकी खेलों की तरह लोकप्रिय बनाने के लिए भारत बड़ा मंच है और यही वजह है कि यहां काफी वैश्विक हाकी टूर्नामेंट आयोजित किए गए हैं। भारत में 2016 पुरुष जूनियर विश्व कप, 2014 चैम्पियंस ट्राफी, 2018 सीनियर पुरूष विश्व कप, 2023 सीनियर पुरुष ट्राफी कप के अलावा महिला और पुरुष एशिया कप और एशियाई चैंपियंस ट्राफी का भी आयोजन किया गया है ।

सेमीफाइनल में जर्मनी से हारा भारत, कांस्य के लिए अर्जेंटीना से भिड़ंत

हाकी

भारत के लिए एकमात्र गोल अनमोल इक्का ने किया। जर्मनी के लिए लुकास कोसेल ने दो, वेक्स टाइटस , जोनास वोन गरसम और बेन हासबाश ने गोल दागे।

चेन्नई, 7 दिसंबर (भाषा)।

लचर डिफेंस और पहले ही हाफ में तीन गोल गंवाने का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा जब सात बार की चैंपियन जर्मनी ने जूनियर हाकी विश्व कप के सेमीफाइनल में रविवार को मेजबान को 5-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब भारतीय टीम 10 दिसंबर को कांस्य पदक के मुकाबले में अर्जेंटीना से खेलेगी जिसे स्पेन ने दूसरे सेमीफाइनल में 2-1 से हराया।

जर्मनी के लिए लुकास कोसेल (14 वां और 30 वां मिनट) ने दो, वेक्स टाइटस (15वां), जोनास वोन गरसम (40 वां) और बेन हासबाश (49वां) ने गोल दागे जबकि भारत के लिए एकमात्र गोल अनमोल इक्का ने 51वें मिनट में किया। दो बार की चैंपियन भारतीय टीम और जर्मनी के प्रदर्शन में जमीन आसमान का अंतर था जो मैच के हर क्षण में नजर आया। मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम पर भारी तादाद में भारत की हौसलाअफजाई करने आए दर्शकों को इस प्रदर्शन से भारी निराशा हाथ लगी।

बेल्जियम को कड़े क्वार्टर फाइनल में शूट आउट में हराने वाली भारतीय टीम पर पहले ही क्वार्टर में ही जर्मनी ने दो गोल करके दबाव बना दिया।

Source:- दैनिक जागरण

फतुहा में विकसित होगी फिनटेक सिटी

गुजरात के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर बनेगी | 242 एकड़ जमीन | अधिग्रहण के लिए 408.81 करोड़ स्वीकृत

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटनाः गुजरात की गिफ्ट की तर्ज पर फतुहा के समीप फिनटेक सिटी को विकसित किया जाएगा। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि 242 एकड़ में विकसित होने वाले फिनटेक सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए 408.81 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

- उद्योग मंत्री बोले- युवाओं को आइटी के क्षेत्र में मिलेंगे अवसर
- उन्नत बुनियादी ढांचा व अनुकूल नीतिगत वातावरण प्रदान करेंगे
- पटना से माल के सीधे निर्यात की उपलब्ध होगी सुविधा

दिलीप जायसवाल • जागरण आर्काइव

वित्तीय सेवाओं, तकनीकी कंपनियों तथा इस क्षेत्र के स्टार्टअप एक जगह आएंगेः उद्योग मंत्री ने बताया कि फिनटेक सिटी में बड़े वित्तीय तकनीकी संस्थानों की उपस्थिति हजारों उच्च कौशल वाले रोजगार का सृजन करेगी। युवाओं को बैंकिंग, वित्त और आइटी के क्षेत्र में यहां अवसर मिलेंगे। फिनटेक सिटी राज्य में इनोवेशन को प्रोत्साहित करेगी।

फिनटेक सिटी के समीप ही लाजिस्टिक पार्कः फिनटेक सिटी के समीप ही मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क को विकसित किया जा रहा। यह माल ढुलाई सेवा से सीधे-सीधे जुड़ी होगी। इससे पटना से माल के सीधे निर्यात की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बिहार से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

तकनीकी क्लस्टर को यहां विकसित किया जाएगाः फिनटेक सिटी में तकनीकी क्लस्टर को विकसित किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि यह पहल बिहार को तकनीक आधारित वित्तीय सेवाओं का बड़ा केंद्र बना सकती है। फिनटेक सिटी के भीतर हम उन्नत बुनियादी ढांचा और अनुकूल नीतिगत वातावरण प्रदान करेंगे, ताकि बैंक, निवेश संस्थान, बीमा कंपनियां, फिनटेक स्टार्टअप और आइटी फर्म यहां आकर अपना काम कर सकें। बिहार में यह पहला अवसर होगा जब बिहार में इतने बड़े पैमाने पर आधुनिक वित्तीय सेवाओं और तकनीकी कंपनियों का संकुल स्थापित होगा। यह राज्य के वित्तीय परिदृश्य को बदल देगा।

औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए बनेगा बीआइएसएफ

पूरी तरह से उद्योगों की सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड इकाई के रूप में करेगी काम, कैबिनेट की मंजूरी के लिए जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटनाः उद्योग मंत्री डा. दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल जल्द ही अस्तित्व में आएगा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआइएसएफ) की तर्ज पर बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (बीआइएसएफ) का गठन किया जाएगा। जल्द ही इस आशय के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बीआइएसएफ उद्योगों की सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड इकाई के रूप में काम करेगी। यह भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी के नेतृत्व में काम करेगा। इसमें डीएसपी व अन्य निरक्षी स्तर के अधिकारी भी रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में इसका मुख्यालय रहेगा। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में नए निवेशक बिहार में उद्योग लगाने की तैयारी में हैं। सरकार ने इसके लिए अलग-अलग क्लस्टर भी बनाए हैं। बीआइएसएफ की सेवा नए निवेशकों को उनके आग्रह पर तो मिलेगी ही साथ में पुराने उद्यमियों के औद्योगिक प्रतिष्ठान को भी सेवा मिलेगी। मालूम हो कि वर्तमान में औद्योगिक इकाइयां अपनी निजी व्यवस्था पर आश्रित हैं। उद्यमियों की पुरानी मांग रही है कि सुरक्षा की संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए।

बिहार में 100 फास्ट ट्रैक अदालतों का होगा गठन, नौ सौ नियुक्तियां भी होंगी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटनाः राज्य में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया जाएगा। जिसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन, न्यायालय का बोझ कम करना और संवेदनशील प्रकृति के मामलों पर उचित ध्यान व समय देना है। प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में 18 लाख से अधिक लंबित मामलों के मद्देनजर ये फास्ट ट्रैक न्यायालय बड़ी राहत देने वाले साबित होंगे। यह जानकारी प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को दी।

उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिलापदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से चिह्नित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करेंगे। राज्य के 38 जिलों और उप-मंडलों में कुल 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने के लिए कर्मियों की नियुक्ति बड़े पैमाने पर की जाएगी। गृह मंत्री के अनुसार प्रत्येक अदालत के लिए आठ प्रकार के पदों जैसे, बेंच क्लर्क, कार्यालय लिपिक, स्टेनोग्राफर, डिपोजिशन राइटर, डेटा एंट्री आपरेटर, ड्राइवर, प्रोसेस सर्वर और चपरासी, आर्डर्ली के कुल 900 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि शस्त्र अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 79 न्यायालयों को एक्ट कोर्ट के रूप में नामित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि शस्त्र अधिनियम जैसे गंभीर मामलों का शीघ्र समाधान कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।

- **सम्राट चौधरी बोले- प्रत्येक अदालत में आठ प्रकार के पदों के लिए नियुक्ति है प्रस्तावित**
- **लंबित आपराधिक तथा संवेदनशील मामलों के त्वरित निपटारे को मिलेगी गति**

सम्राट चौधरी ● जागरण आर्काइव

पटना में बनेंगी आठ फास्ट ट्रैक कोर्ट

अकेले पटना में आठ फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में चार-चार अदालतें स्थापित की जाएंगी। नालंदा (बिहारशरीफ), रोहतास (सासाराम), सारण (छपरा), बेगूसराय, वैशाली (हाजीपुर), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), समस्तीपुर और मधुबनी में तीन-तीन फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। पश्चिमी चंपारण (बेतिया), सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर (भभुआ), बक्सर, भोजपुर (आरा), सीतामढ़ी, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय और खगड़िया में दो-दो, नवगछिया और बगहा उप-मंडलीय न्यायालय में एक-एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगी।

एक नई विश्व व्यवस्था की दस्तक

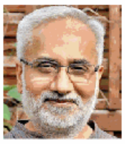

शिवकांत शर्मा

ट्रंप के धौंस भरे रवैये ने रूस, चीन और भारत को एक-दूसरे के निकट ला दिया। इस तिकड़ी को नई विश्व व्यवस्था की उभरती धुरी के रूप में देखा जा रहा है

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने एक भाषण में कहा था कि पश्चिम का राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व समाप्त हो रहा है और विश्व की अगली व्यवस्था कम से कम दो ध्रुवीय या फिर बहुध्रुवीय होगी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डर लेन ने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे पश्चिम और शेष विश्व के बीच सहयोग के नए आयाम खुल सकेंगे। गत सितंबर में तियानजिन के एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि एससीओ एक बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। उसी सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने एक विश्व संचालन पहल का प्रस्ताव रखा था और अधिनायकवाद एवं धौंस की राजनीति के खिलाफ खड़े होकर सच्ची बहुपक्षीयता पर चलने का आह्वान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर तंज करते हुए इसे अमेरिका के खिलाफ साजिश कहा, पर दुनिया भर के राजनयिकों ने इसे एक नई उभरती विश्व व्यवस्था की दस्तक के रूप में देखा था।

राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा को उसी की एक और कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप ने भारत के साथ 25 साल पुरानी दोस्ती को ताक पर रखते हुए रूस से तेल खरीदने के विरोध में टैरिफ बढ़ाकर दोगुना कर दिया जिनकी वजह से भारत का अरबों डालर का निर्यात प्रभावित हुआ है। बीते कुछ वर्षों में अमेरिका भारतीय वस्तुओं की सबसे बड़ी मंडी बनकर उभरा, जहां पिछले साल तक 87 अरब डालर का निर्यात होता था जो भारत के कुल निर्यात का करीब 20 प्रतिशत है। दूसरी तरफ रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुक आयल पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे रूस को अरबों डालर का नुकसान हो रहा है। ट्रंप की शैली भी धौंस दिखाने की है। यही शिकायत चीन को भी है। इसलिए कहां तो वे सत्ता संभालते ही किसिंजर नीति पर चलते हुए रूस को चीनी प्रभाव से निकाल कर अपनी तरफ करने का दम भर रहे थे और कहां उनकी अप्रत्याशित नीतियों और धौंस ने रूस, चीन और भारत को एक-दूसरे के और निकट कर दिया। रूस, भारत और चीन की इस यूरेशियाई तिकड़ी या रिक को नई विश्व व्यवस्था की उभरती धुरी के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया की 40 प्रतिशत जीडीपी और जनशक्ति, प्रबल सैन्य शक्ति और दक्षिणी देशों में प्रभाव और साख होने के कारण इन तीनों के बढ़ते प्रभाव की अवहेलना नहीं की जा सकेगी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आकार लेते नए समीकरण, जिसमें भारत की होगी अहम भूमिका ● फाइल

आधुनिक चीन का लक्ष्य अपने शताब्दी वर्ष 2049 तक विश्व में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की धुरी बनकर अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कद की बराबरी पर आना है। ट्रंप की मनमानी नीतियों ने उसका काम और आसान बना दिया है। रूस का लक्ष्य सोवियत संघ के विघटन से खोए वर्चस्व को बहाल करते हुए अपने आभा क्षेत्र का विस्तार करना है, जिसे वह नाटो का विस्तार रोककर और यूरेशिया में अपना प्रभाव फैलाकर हासिल करना चाहता है। उसने यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और नाटो को चुनौती देकर अपनी सामरिक और आर्थिक धाक को काफी हद तक बहाल कर लिया है। करीब ढाई लाख सैनिकों और 1200 अरब डालर के नुकसान के बावजूद उसकी सेना आगे बढ़ रही है। आर्थिकी ठप नहीं हुई है और पश्चिमी देश उसकी घेराबंदी में नाकाम रहे हैं। रूस और चीन दोनों अपनी रक्षा तकनीक और सैनिक साजोसमान के मामले में नाटो और अमेरिका की तरह आत्मनिर्भर हैं। चीनी सामरिक क्षमता की अभी तक रूस की तरह युद्ध के मैदान में परीक्षा नहीं हुई है, लेकिन उसने आर्थिक और तकनीकी शक्ति के मामले में ट्रंप को झुकने पर मजबूर करके अपनी शक्ति दिखा दी है। जार्ज आरवेल के उपन्यास '1984' की तरह अभी शक्ति की तीन धुरियां बनती दिख रही हैं। भारत को चौथी धुरी बनने के लिए सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर बहुत कुछ करना है, परंतु उसकी जनशक्ति और आर्थिक एवं तकनीकी विकास की संभावनाएं उसे किसी भी नई विश्व व्यवस्था में अपरिहार्य बनाती हैं। इसी की ओर इशारा करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने भारत यात्रा से पहले दिए एक इंटरव्यू में जी-7 जैसे संगठनों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया था, जिनमें न भारत है और न रूस और चीन।

कोई भी नई व्यवस्था केवल पुरानी व्यवस्था के विरोध की नींव पर खड़ी नहीं हो सकती। यह सही है कि ट्रंप ने पहले से ही अमेरिका और नाटो की दोहरी नीतियों की वजह से कमजोर और अप्रासंगिक होती आ रही विश्व व्यवस्था को अपनी मनमानी और अस्थिर नीतियों से और छिन्न-भिन्न कर दिया है। पहले संयुक्त राष्ट्र की किसी भी संस्था में दिखावे के लिए भी कोई प्रस्ताव रखे बिना ईरान पर हमला किया और अब वेनेजुएला की नौकाओं पर हमले कर रहे हैं। यूक्रेन की मर्जी के बिना उसकी जमीन रूस को सौंपकर शांति समझौता लादना चाहते हैं। मनमाने टैरिफ थोपकर विश्व व्यापार संगठन को अप्रासंगिक बना दिया है। जलवायु संधि, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को सदस्यता छोड़ दी, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन और महामारियों का सामना कर पाने और विश्व धरोहरों की रक्षा कठिन हो गई। अमेरिका ने अपने नेतृत्व में जो नियमबद्ध विश्व व्यवस्था शुरू की थी, उसे ट्रंप 'जिसकी लाठी-उसकी भैंस' वाली व्यवस्था में बदलते जा रहे हैं। इससे चिंतित होकर चीन, रूस और भारत निकट जरूर आए हैं, पर विश्व व्यवस्था को लेकर तीनों के बीच गहरे विरोधाभास रहे हैं। चीन जिहादी आतंकवाद, परमाणु निरस्त्रीकरण और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर टांग अड़ाता रहा है। रूस ने स्वतंत्र देशों की सार्वभौमिता और अखंडता के सिद्धांत को ताक पर रखकर यूक्रेन पर हमला किया है और चीन ताइवान पर हमले की ताक में है। चीन मुक्त व्यापार के नियमों का भी पालन नहीं करता, जिसकी वजह से भारत को भारी व्यापार घाटा हो रहा है। ऐसे में तीनों के बीच किसी नियमबद्ध वैश्विक व्यवस्था पर सहमति कैसे संभव होगी? हो भी गई तो अमेरिका और यूरोप को उसके पालन के लिए कैसे मनाया जा सकेगा? यह भी कि रूस से मिली हार और अमेरिका से मोहभंग के बाद अब यूरोप की भूमिका क्या रहेगी?

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)
response@jagran.com

प्रवासी पक्षी मादा ग्रेलैग गूज अब सोनवर्षा के नाम से जानी जाएगी

मिथिलेश कुमार, जागरण बिहपुर (भागलपुर) :

सोनवर्षा गंगा दियारा के घटोरा वेटलैंड में शुक्रवार को भागलपुर जिले का पहला जीपीएस टैगिंग अभियान पूरा किया गया। यह बिहार में प्रवासी पक्षियों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार और बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस) के संयुक्त उपक्रम बर्ड रिंगिंग एंड मानिटरिंग स्टेशन भागलपुर ने यहां एक मादा ग्रेलैग गूज को जीपीएस-जीएसएम टैग किया। टैगिंग के बाद इस पक्षी का नाम "सोनवर्षा" रखा गया, जो उसी गांव के सम्मान में है जहां इसे पकड़ा गया। रविवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी।

सोनवर्षा शब्द उपजाऊ, सुनहरी नदी-जनित भूमि का प्रतीक माना जाता है। विभाग द्वारा जारी जानकारी

बिहपुर के घटोरा वेटलैंड में पक्षियों की जीपीएस टैगिंग करते अधिकारी। सौ.बीएनएचएस

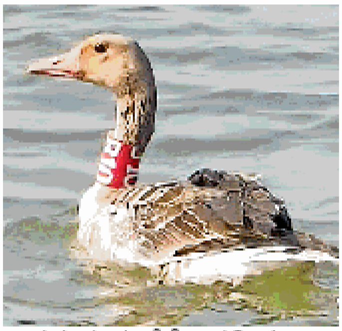

घटोरा वेटलैंड में जीपीएस टैगिंग के बाद मादा ग्रेलैग गूज। सौ. बीएनएचएस

में कहा गया कि यह पहल प्रवासी पक्षियों के प्रवासन मार्ग, ठहराव स्थल और आवास उपयोग से जुड़ी अहम जानकारी जुटाने में मदद करेगी। इससे वेटलैंड संरक्षण और जलवायु से जुड़े अध्ययनों को भी मजबूती मिलेगी। अभियान बीएनएचएस के डिप्टी डायरेक्टर डा. पी. सथियासेल्वम के नेतृत्व में संचालित हुआ।

जानिए ग्रेलैग गूज पक्षी के बारे में : ग्रेलैग गूज उत्तरी यूरोप, रूस और मध्य एशिया में प्रजनन करने वाली लंबी दूरी की प्रवासी प्रजाति है। सर्दियों में यह दक्षिण एशिया की ओर उड़ान भरते हुए हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है। भारत में यह मुख्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के बड़े वेटलैंड्स में दिखाई देते हैं। यहां शीतकालीन प्रवास करते हैं।

एनईपी पर चली प्रदेश की शिक्षा को मिलेगी और तेज रफ्तार

उच्च शिक्षा विभाग के सृजन से अनुसंधान व नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

दीनानाथ साहनी ● जागरण

पटना : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) आने के बाद बिहार की पूरी शिक्षा नए रास्ते पर चल पड़ी है। हालांकि इसकी मंजिल और रास्ते दोनों ही चुनौतीपूर्ण हैं। इसमें स्कूली शिक्षा से शत प्रतिशत नामांकन को हासिल करना, ड्रापआउट रोकने तथा गुणवत्ता लाने, उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात (जीइआर) को वर्ष 2030 तक 30 प्रतिशत करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात को बेहतर बनाने सहित उसके लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को जुटाने जैसी चुनौतियां शामिल हैं।

उच्च शिक्षा में जीइआर बढ़ाने की चुनौती तब और बढ़ गई है, जबकि केंद्र सरकार ने 2035 तक उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में बिहार का जीइआर करीब 20 प्रतिशत है।

- समग्र गुणात्मक सुधार को मानीटरिंग और प्लानिंग करने में होगी सुगमता
- पीएम श्री स्कीम में प्रत्येक प्रखंड के कम से कम दो विद्यालयों को किया जाएगा अपग्रेड

शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एनईपी को लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। तभी तो उच्च शिक्षा में समग्र गुणात्मक सुधार लाने, अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग का सृजन किया गया है। इसके गठन के बाद उच्च शिक्षा विभाग संबंधी प्रशासनिक ढांचा में बड़ा बदलाव किया जाएगा। इससे उच्च शिक्षा में समग्र गुणात्मक सुधार लाने हेतु बेहतर प्लानिंग करने में सुगमता होगी। वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों की मानीटरिंग करने और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। अगर उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात (जीइआर) को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत करने का राष्ट्रीय लक्ष्य है तो बिहार को भी तय अवधि में उक्त लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करनी होगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक 2030 तक प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थान में तब्दील करने का लक्ष्य है। माना जा रहा है कि इस पहल से उच्च शिक्षा के लिए होने वाला छात्रों का पलायन भी थमेगा। साथ ही शहरी क्षेत्रों में मौजूद उच्च शिक्षण संस्थानों पर से दबाव भी हटेगा। उच्च शिक्षा में छात्र-छात्राओं के लिए फीस में एकसमानता का मानक भी जल्द तय होगा। अभी राज्य में विश्वविद्यालयों की फीस में विभिन्नता है।

शिक्षा सुधारों में केंद्र से कदमताल मिलाकर बिहार चलने को हो रहा तैयार

हाल में केंद्र सरकार ने शिक्षा सुधारों को रफ्तार देने और तालमेल बनाकर काम करने की जरूरत बताई है। इससे सहमति जताते हुए बिहार भी केंद्र के साथ तालमेल बैठाकर चलने के लिए तैयारी में है। पीएम श्री स्कीम इसका एक बड़ा उदाहरण भी है, जिसे अभी भी कई राज्यों ने नहीं अपनाया है। वहीं बिहार ने इस स्कीम को अपनाकर अब तक 200.35 करोड़ रुपये का केंद्रीय मदद हासिल कर चुका है। इस स्कीम के तहत प्रत्येक प्रखंड के कम से कम दो स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है। शिक्षा सुधारों को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि एनईपी के अमल के लिए केंद्र, राज्य, नियामक एजेंसियों व शैक्षणिक संस्थानों को साथ कदमताल करनी होगी। स्कूलों के ड्राप आउट एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर में और तेजी से सुधार करने होंगे।

पीएम सूर्य घर योजना में 23.9 लाख रूफटाप सोलर लगाए गए

नई दिल्ली, एएनआइः प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत दिसंबर 2025 तक देश के 23.9 लाख घरों में रूफटाप सोलर प्रणाली लग चुकी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इससे सात गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। राष्ट्रीय सौर मिशन ने बड़े सौर पार्कों, छत पर सौर प्रणालियों और हाइब्रिड परियोजनाओं का भी समर्थन किया है, जिससे भारत अपने दीर्घकालिक ऊर्जा लक्ष्यों के करीब पहुंच रहा है। योजना के तहत एक करोड़ घरों में रूफटाप सोलर प्रणाली लगाई जानी है।

बयान के अनुसार, पिछले एक दशक में देश में सौर ऊर्जा स्थापना में तेज वृद्धि हुई है जिसने देश की कुल बिजली क्षमता को दोगुना करने में मदद की है। अब देश में कुल 129 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, जबकि अक्टूबर 2025 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 259 गीगावाट को पार कर चुकी है। इसका मतलब है कि देश की कुल स्थापित बिजली का आधे से अधिक हिस्सा अब स्वच्छ स्रोतों से उत्पादित हो रहा है।

योजना के तहत सात गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन, 129 गीगावट पर पहुंचा देश में कुल सौर ऊर्जा उत्पादन

भारत काप-26 में घोषित पंचामृत ढांचे के अनुरूप स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके तहत 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कार्बन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कटौती की जानी है। यह लक्ष्य भारत के नवीकरणीय ऊर्जा प्रयासों की गति और पैमाने को आगे बढ़ाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2014 में देश में केवल तीन गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा था, जो अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 129 गीगावाट हो गया है।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को कर्ज देने पर रोक नहीं

एमएनआरई ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में **जरूरत से ज्यादा क्षमता** होने संबंधी खबरों को पूरी तरह से गलत बताया

- सरकार ने कहा, भारतीय वित्तीय संस्थानों को कर्ज रोकने संबंधी कोई सलाह नहीं दी
- पीएफसी, आरईसी और आइआरईडीए की नवीकरणीय परियोजनाओं की स्थिति साझा की

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने इस बात को खारिज किया है कि उसकी तरफ से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं या इन परियोजनाओं से जुड़े उपकरण निर्माण उद्योग को कर्ज नहीं देने के लिए भारतीय वित्तीय संस्थानों को कोई सलाह दी गई है। रविवार को एमएनआरई ने इस बारे में स्पष्ट किया कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में जरुरत से ज्यादा क्षमता होने संबंधी खबरें पूरी तरह से गलत है। मंत्रालय ने वित्तीय सेवा देने वाले विभागों और पीएफसी, आरइसी तथा आइआरईडीए जैसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सौर पीवी मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में देश में स्थापित की जाने वाली विनिर्माण क्षमताओं की स्थिति साझा की है, ताकि वो इन परियोजनाओं से जुड़े लोन आदि का मूल्यांकन संतुलित तरीके से कर सकें।

एमएनआरई ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत सरकार सौर पीवी मैन्यूफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता हासिल करने और भारत को इस क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को समर्थन देने के लिए ही उच्च दक्षता वाले सौर पीवी माड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना लागू की गई है। साथ ही भारतीय मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को दूसरे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इन प्रोत्साहनों से ही सौर माड्यूल मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता जो 2014 में मात्र 2,300 मेगावाट थी, वह अब 1.22 लाख मेगावाट हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि वह सेक्टर के सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करता रहेगा ताकि भारतीय सौर ऊर्जा सेक्टर को प्रतिस्पर्द्धी और भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।

मंत्रालय की तरफ से इस स्पष्टीकरण के बावजूद वस्तुस्थिति कुछ अलग है। वित्तीय संस्थानों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लेकर कुछ चिंताएं हैं। अफवाह की जड़ आल इंडिया सोलर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एआइएसआइए) की तरफ से इसी वर्ष नवंबर में एमएनआरई को लिखा गया एक पत्र है जिसमें सौर माड्यूल मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता में तेजी से विस्तार से गंभीर अतिरिक्त क्षमता सृजित होने की चेतावनी दी गई थी। एसोसिएशन ने बताया कि भारत की माड्यूल क्षमता देश की वार्षिक जरूरत से लगभग चार गुना हो चुकी है। जिससे निवेश के फंसने और कीमतों पर दबाव का खतरा है। इससे सतर्क होते हुए एमएनआरई ने चार दिसंबर को एक आफिस मेमोरैंडम जारी किया गया। इसमें वित्तीय सेवा विभाग और एनबीएफसी (जैसे पीएफसी, आरईसी, आइआरईडीए) को सौर पीवी विनिर्माण के विभिन्न चरणों (माड्यूल, सेल, इंगाट-वेफर, पालीसिलिकान आदि) में वर्तमान क्षमताओं की स्थिति साझा की गई। मंत्रालय ने सलाह दी कि नई परियोजनाओं के वित्तपोषण संबंधी मूल्यांकन में सतर्कता बरती जाए और फंडिंग को सेल, वेफर और पालीसिलिकान जैसे अपस्ट्रीम सेक्टर की तरफ मोड़ा जाए।

नवीकरणीय क्षेत्र से पांच लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य

भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से पांच लाख मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। 31 अक्टूबर 2025 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से स्थापित क्षमता लगभग 2.59 लाख मेगावाट है। इसमें वित्त वर्ष 2025-26 में अक्टूबर के अंत तक 31.2 गीगावाट की वृद्धि हुई है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश की आवश्यकता है। एक अध्ययन के मुताबिक, वर्ष 2023 तक सौर, पवन समेत सभी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तीन लाख मेगावाट बिजली क्षमता जोड़ने के लिए 500 अरब डालर की जरूरत होगी।

2035 के बाद कोयला ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की तत्काल कोई योजना नहीं : सचिव

नई दिल्ली, रायटर : बिजली मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने रविवार को स्पष्ट किया कि भारत की 2035 के बाद कोयला ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोई तत्काल योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित करना चाहता है। 2035 तक हम 307 गीगावाट की कोयला क्षमत चाहते हैं। 2035 के बाद हम क्या करना चाहते हैं, यह कहना जल्दबाजी होगी। इसी वर्ष भारत ने अपनी कोयला ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 210 गीगावाट से 46 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

जल्द दिखने लगेगा कोसी-मेची परियोजना का काम

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना: लगभग एक दशक की प्रतीक्षा के बाद, अगले वर्ष की शुरुआत में, कोसी-मेची नदी जोड़ो परियोजना का निर्माण-कार्य धरातल पर शुरू हो जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य सिंचाई नेटवर्क के विस्तार के साथ कोसी परिक्षेत्र व सीमांचल में बाढ़ के खतरे का प्रबंधन करना भी है।

परियोजना के पहले चरण के निष्पादन के लिए लगी निर्माण कंपनी (ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) मौजूदा नहर का सर्वेक्षण कर रही। सर्वेक्षण और डिजाइन का काम दिसंबर तक पूरा होने के बाद धरातल पर काम शुरू होने की संभावना है। यह कार्य टर्न-की आधार पर आवंटित है, जिसके अंतर्गत निर्माण कंपनी को 2682.73 करोड़ रुपये की लागत से जमीनी कार्य शुरू करने से पहले सर्वेक्षण, डिजाइन और ड्राइंग का काम पूरा करना है।

6282.32 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण मार्च, 2029 तक पूरा करना है। इसके अंतर्गत कोसी से मेची में अतिरिक्त पानी के स्थानांतरण से बाढ़ का खतरा काफी कम हो जाएगा।

इसके साथ ही सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिलों में अतिरिक्त 2.14 लाख हेक्टेयर परिक्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा। निर्माण कंपनी को गाद प्रबंधन का एक स्थायी तरीका भी विकसित करना है, जो पुराने चैनल के लिए अभिशाप रहा है। चूंकि नहर मुख्य रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए नेपाल से अनियंत्रित पानी के प्रवाह के कारण उत्तर ओर एक बड़ा भूभाग वर्षा-ऋतु में जलमग्न हो जाता है। नए डिजाइन में जलभराव को दूर करने के लिए क्रास रेगुलेटर और नहर साइफन की परिकल्पना की गई है।

- **परियोजना को मार्च, 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य, 6282.32 करोड़ रुपये होने हैं खर्च**
- **गाद प्रबंधन का स्थायी तरीका भी विकसित होगा, क्रास रेगुलेटर व नहर साइफन भी बनेंगे**

2.14 लाख हेक्टेयर परिक्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा

8 जिलों में बड़े भूभाग और बड़ी जनसंख्या को बाढ़ से मिलेगी मुक्ति

परियोजना के दो चरण

- **पहला चरण :** बीरपुर से हनुमान नगर तक 41 किलोमीटर लंबी कोसी नदी की पूर्वी मुख्य नहर को मजबूत किया जाएगा, ताकि जल वहन क्षमता 15000 क्यूसेक से बढ़ाकर 20000 क्यूसेक हो सके। इस चरण के अंतर्गत ड्रोन सर्वे, एलाइनमेंट सत्यापन और भूमि सर्वेक्षण चल रहा है।
- **दूसरा चरण :** नेपाल सीमा के समानांतर 76 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, नहर को महानंदा की सहायक मेची नदी तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा डीपीआर को अंतिम रूप दिए जाने के बाद जल संसाधन विभाग भूमि अधिग्रहण शुरू करेगा।

मुख्य लक्ष्य

कोसी नदी के अधिशेष जल को पूर्वी कोसी मुख्य नहर के माध्यम से महानंदा बेसिन की मेची नदी में ले जाना है। इससे वर्षा-ऋतु में अतिरिक्त पानी को नियोजित रूप से मोड़ा जाएगा, जिससे कोसी बेसिन में बाढ़ का खतरा कम होगा।

सिंचाई विस्तार : अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों के लगभग 2.15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसमें चार शाखा नहर और छह वितरणियां सम्मिलित होंगी।

नहर की लंबाई

नहर की कुल लंबाई 117 किमी होगी, जिसमें वर्तमान पूर्वी कोसी मुख्य नहर का 76.2 किमी विस्तार सम्मिलित है। यह नेपाल सीमा के निकट मेची नदी तक पहुंचेगी।

हैदराबाद को हराकर मुंबई ने जीता खिताब

INDIAN PICKLEBALL LEAGUE

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: मुंबई स्मैशर्स ने इंडियन पिकलबाल लीग (आइपीबीएल) के ग्रैंड फिनाले में हैदराबाद रायल्स को हराकर इतिहास रच दिया। लीग में मुंबई ने छठे स्थान से शुरू करने के बाद वापसी करते हुए खिताब अपने नाम किया। रविवार को केडी जाधव इनडोर हाल में हुए मुकाबले में मुंबई ने हैदराबाद को 5-1 से मात दी। इस मुकाबले के दौरान संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजीजू भी मौजूद रहे।

हैदराबाद ने लीग की अच्छी शुरुआत की और ग्रुप स्टेज दूसरे स्थान पर खत्म किया। वहीं, मुंबई ने शुरुआती मुकाबले हारने के बाद अंतिम लीग टाई में गुरुग्राम को हराकर प्ले-इन में मौका पाया और इसके बाद लगातार जीत दर्ज करते

विजेता टीम के साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ● आइपीबीएल

हुए एलिमिनेटर में लखनऊ और क्वालिफायर-2 में चेन्नई को हराकर फाइनल में जगह बनाई।

फाइनल में क्वांग डुओंग ने शानदार प्रदर्शन किया, पहले तेजस गुलाटी को 15-4 से हराया और बाद में अमोल रामचंदानी के साथ मिलकर पुरुष डबल्स में बेन न्यूवेल और दिव्यांशु कटारिया को 15-10 से मात दी। इसके बाद मेगन फज ने हैदराबाद के लिए उम्मीद जगाते हुए महिलाओं के सिंगल्स में 15-5 से जीत दर्ज की। लेकिन मुंबई ने एलिसन हैरिस और पर्ल अमलसाड़ीवाला की जोड़ी की 15-10 की जीत के साथ मजबूत वापसी की। ग्रैंड रैली में मुंबई ने 6-1 से बढ़त बनाई। हैदराबाद ने स्कोर 8-5 तक लाकर मुकाबला जीवंत रखा, लेकिन मुंबई ने नियंत्रण बरकरार रखते हुए 21-14 से खिताब जीत लिया। डुओंग और पर्ल को प्लेयर आफ द टाई चुना गया।